vinetur

फ्रांस के 2027 बजट में कृषि निवेश पर 40% की अतिरिक्त कर-कटौती

तीन साल की इस प्रोत्साहन योजना के साथ मौजूदा टैक्स क्रेडिट और मौसमी श्रमिकों के लिए पेरोल राहत भी जारी रहेगी।

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026



फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सरकार के 2027 के बजट पैकेज में कृषि भवनों और उपकरणों पर 40% की नई अतिरिक्त कर-कटौती शामिल होगी। साथ ही, कई मौजूदा टैक्स क्रेडिट बरकरार रखे जाएंगे और मौसमी कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक पेरोल राहत जारी रहेगी।

मंत्रालय ने ये ब्योरे ऐसे समय जारी किए हैं, जब सांसद 2027 के मसौदा बजट और उससे जुड़े सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण विधेयक की समीक्षा शुरू कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक, यह व्यापक पैकेज निवेश, कृषि व्यवसायों के हस्तांतरण और भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए है। 2026 की कठिन गर्मियों का कई कृषि परिचालनों पर गंभीर असर पड़ा था।

मंत्रालय के अनुसार, 2027 के वित्त विधेयक में कृषि और खाद्य क्षेत्र के लिए बजट €4 billion है। कृषि शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए धनराशि जोड़ने पर यह आंकड़ा €6 billion हो जाता है। मंत्रालय ने यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति के तहत €9.4 billion की सहायता और सामाजिक तथा कर उपायों के लिए €9 billion का भी उल्लेख किया। उसके मुताबिक, इससे कृषि के लिए समग्र सार्वजनिक सहायता ढांचा लगभग €25 billion का हो जाता है।

सरकार ने 1 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के सामने 2027 का वित्त विधेयक पेश किया था। कृषि संघ पहले ही कह चुके हैं कि बजट पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि मौसम से हुए नुकसान और कृषि आय पर अन्य दबावों के बाद इस क्षेत्र को और मजबूत सहायता की जरूरत है। मंत्रालय ने सोमवार के बयान में कहा कि €1 billion से अधिक की आपातकालीन सूखा योजना, जिसे पहले ही लागू किया जा रहा है, 2027 के लिए नियोजित संसाधनों के अतिरिक्त होगी।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि अलग से तैयार की जा रही कृषि पुनर्बहाली योजना का मकसद 2027 के बजट पर संसदीय बहस को दिशा देना है। इस बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्तों में विधेयकों की समीक्षा के दौरान मौजूदा पैकेज में बदलाव हो सकते हैं।

मंत्रालय ने जिस मुख्य नए कर उपाय का ब्योरा दिया, वह भवनों और प्रतिष्ठानों में निवेश पर तीन साल के लिए उपलब्ध 40% की अतिरिक्त कर-कटौती है। सरकार ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य उन निवेशों को प्रोत्साहन देना है जो फ्रांस की खाद्य संप्रभुता को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं। खाद्य संप्रभुता के लिए एक नया सीड फंड भी शुरुआती चरण की परियोजनाओं को सहायता देने वाला है, हालांकि मंत्रालय के बयान में इसके संचालन के विस्तृत नियम या क्षेत्रवार आवंटन नहीं दिए गए।

इस नए प्रोत्साहन के साथ, सरकार ने कहा कि 2027 के बजट में कई मौजूदा सहायता उपाय जारी रखने की योजना है। इनमें जैविक खेती के लिए टैक्स क्रेडिट, उच्च पर्यावरणीय मूल्य प्रमाणन प्राप्त कृषि व्यवसायों के लिए टैक्स क्रेडिट—जिसे फ्रांस में HVE के नाम से जाना जाता है—किसानों द्वारा आय में उतार-चढ़ाव को संभालने और जोखिम प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एहतियाती बचत कटौती, तथा कृषि व्यवसायों के हस्तांतरण और नई कृषि इकाइयां शुरू करने को आसान बनाने वाले उपाय शामिल हैं।

श्रम के मोर्चे पर मंत्रालय ने कहा कि 2027 के सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण विधेयक में TO-DE प्रणाली के तहत अस्थायी कृषि श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं के सामाजिक अंशदान से छूट जारी रहेगी। मंत्रालय ने इस उपाय की लागत लगभग €600 million बताई, जो €9.4 million अधिक है। यह राहत लंबे समय से कृषि नियोक्ताओं के लिए अहम मुद्दा रही है, खासकर उन नियोक्ताओं के लिए जो कटाई के मौसम में अल्पकालिक श्रम पर निर्भर रहते हैं।

यह बात व्यापक कृषि अर्थव्यवस्था से परे भी मायने रख सकती है। फ्रांस के वाइन क्षेत्र में अंगूर की कटाई के दौरान श्रम की मांग तेजी से बढ़ती है और मौसमी पेरोल लागत उत्पादकों के मुनाफे पर भारी पड़ सकती है। इसलिए, अंशदान में राहत जारी रहने से अंगूर के बागों को भर्ती लागत संभालने में मदद मिल सकती है। निवेश संबंधी कर उपाय उन वाइन उत्पादकों के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं जो कृषि भवनों, प्रसंस्करण सुविधाओं या अन्य उपकरणों पर काम की योजना बना रहे हैं। इसी तरह के प्रभाव फल और साइडर, स्पिरिट्स तथा अन्य पेय पदार्थों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कृषि इनपुट की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों तक भी पहुंच सकते हैं—यह अंतिम उपायों के दायरे पर निर्भर करेगा।

मंत्रालय ने इस पैकेज को मौजूदा सहायता बरकरार रखते हुए लक्षित निवेश साधन जोड़ने के तरीके के रूप में पेश किया। हालांकि, कई ब्योरे अभी संसदीय प्रक्रिया पर निर्भर हैं। वित्त विधेयक और सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण विधेयक—दोनों को नेशनल असेंबली और सीनेट से पारित होना होगा। वहां विपक्षी दलों, कृषि समूहों और क्षेत्रीय सांसदों से वित्तपोषण के स्तर, श्रम लागत और जलवायु संबंधी सहायता में बदलाव की मांग की उम्मीद है।

यह घोषणा ऐसे समय आई है जब फ्रांस की कृषि नीति पर एक साथ कई दिशाओं से दबाव है : बार-बार मौसम की मार, भवनों और उत्पादन प्रणालियों को अनुकूल बनाने की लागत, और कृषि में पीढ़ीगत बदलाव को लेकर लंबे समय से चली

आ रही चिंताएं। जैविक खेती और HVE-प्रमाणित कृषि व्यवसायों के लिए सहायता जारी रखने के सरकार के फैसले पर उन उत्पादकों की करीबी नजर रहने की संभावना है, जिन्होंने इन प्रणालियों में निवेश किया है और कर नीति में दीर्घकालिक स्पष्टता की मांग की है।

पूंजीगत खर्च पर विचार कर रहे कृषि व्यवसायों के लिए नई 40% की अतिरिक्त कर-कटौती इस पैकेज के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। व्यावहारिक रूप से, ऐसा उपाय तय अवधि के दौरान पात्र निवेश पर कर संबंधी लाभ दे सकता है और सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कर-पश्चात लागत घटा सकता है। इस प्रोत्साहन का व्यापक असर होगा या नहीं, यह अंतिम कानूनी पाठ, पात्रता नियमों और वित्तीय दबाव झेल रहे कृषि व्यवसायों की बड़ी परियोजनाओं पर आगे बढ़ने की क्षमता पर निर्भर करेगा।

सरकार ने सोमवार के पैकेज को अंतिम निर्णय के रूप में पेश नहीं किया है। घोषणा को आगामी कृषि पुनर्बहाली योजना और संसदीय बजट बहस से जोड़कर मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रस्ताव इस व्यापक बातचीत का हिस्सा हैं कि 2027 में फ्रांस की कृषि को कितनी सहायता मिलेगी और निवेश, श्रम, जोखिम प्रबंधन तथा पर्यावरण नीति के बीच उसका वितरण कैसे होगा।